

Government of India  
Ministry of Environment & Forests  
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,  
Aliganj, Jor Bagh Road,  
New Delhi: 110003

**Dated: 23<sup>rd</sup> August, 2021**

To

The Regional Officer  
Integrated Regional Office  
MoEF&CC, Raipur  
Chhattisgarh

**Sub: Proposal for non-forestry use of 402.966 ha of forest land in favour of M/s South Eastern Coalfield Limited for Kusmunda and Laxman Opencast Coal Mining Projects in Korba District of Chhattisgarh – reg.**

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 24.04.2018 on the above subject conveying the Stage-I approval to the State Government and Government of Chhattisgarh's letter no. 5-04/2007/201-2 dated 5<sup>th</sup> April, 2021, forwarding a report on the compliance of conditions stipulated in the Stage-I approval dated 26.04.2018. In this connection, it is to inform that a report from the Integrated Regional Office, Raipur in compliance to conditions no. (ii) of Stage-I approval is awaited. Comments of the State Government in compliance of said condition is enclosed herewith.

In view of the above, the IRO is requested to submit its report in compliance to condition no. (ii) of the Stage-I and comments on the submissions made by the State Government at the earliest.

Yours faithfully,

Sd/-

**(Charan Jeet Singh)**

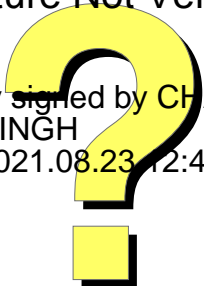
Scientist 'D'

Copy to:

1. The PCCF (HoFF), Government of Chhattisgarh, Raipur.
2. The Addl. PCCF & Nodal Officer (FCA), Jail Road, Aranya Bhavan, Raipur
3. User Agency
4. Monitoring Cell, FC Division, MoEF&CC, New Delhi
5. Guard file

Signature Not Verified

Digitally signed by CHARAN  
JEET SINGH  
Date: 2021.08.23 12:46:51 IST



**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

क्रमांक/एफ 5-04/2007/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05/04/2021  
प्रति,

**डी.आई.जी. (एफ.सी.)**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा  
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़  
नई दिल्ली - 110003।

**विषय:-** Diversion of 402.966 ha of forest land for Kusmunda & Laxman Opencast Mining of Coal in favour of SECL in Korba District of Chhattisgarh.

- संदर्भ:-** 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-08/2018-FC, दिनांक 26.04.2018।  
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/104/187, दिनांक 25.01.2021।

---00---

विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 26.04.2018 के माध्यम से सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय की गई है।

2/- उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 2 दिनांक 25.01.2021 के माध्यम से प्रेषित की गई है, जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

**(के.पी.राजपूत)**

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5-04/2007/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05/04/2021  
प्रतिलिपि :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग





कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़  
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002  
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - मू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./मू-प्रबंध/खनिज/104/ 187

रायपुर, दिनांक 25/01/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन  
नवा रायपुर

विषय:— Diversion of 402.966 ha of forest land for Kusmunda & Laxman Open cast Mining of Coal in favour of South Eastern Coalfields Limited.

- संदर्भ: — 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र F. 8-08/2018-FC दिनांक 26.04.2018  
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ त.अ./3341 दिनांक 31.12.2019 एवं पत्र क्रमांक/ 3062 दिनांक 29.12.2020

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र-1 द्वारा SECL को कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल अंतर्गत कुसमुण्डा एवं लक्ष्मण खुली खदान 402.966 हे. वन भूमि में कोयला उत्खनन हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

संदर्भित पत्र -2 के माध्यम से प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:—

SL	CONDITIONS	Compliance
1)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (संलग्नक-01)
2)	Since the SECL has willfully violated the provisions of Forest Conservation Act and though obtained the environment clearance (EC) but continued mining without the FC under section 2(ii) of FC Act. Therefore, strict action under section 3A/3B of FC Act against the in-charge of the Kusmunda OCP should be initiated by Regional office, Nagpur.	उक्त प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा भूमि का अधिग्रहण शासकीय भूमि के मद में किया गया था जिसका नोईयत छोड़े बड़े झाड़ के जंगल है। दिनांक 12.12.1996 के माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश के तहत उक्त छोड़े बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि राजस्व वनभूमि के नियमितकरण प्रस्ताव तीन चरणों में जमा किया गया था जिसे एकत्रित कर 402.966 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव पूर्व में जमा किया गया था। उक्त राजस्व वनभूमि का उपयोग आवेदक संस्था द्वारा भवनो का निर्माण, खनन आदि कार्यों में 25.10.1980 के पूर्व 20. 671 हे. एवं शेष 25.10.1980 से 12.12.1996 के मध्य उपयोग किया गया है। पूर्व में प्रभावित छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद के भूमि को शासकीय भूमि के रूप में उपयोग



		किया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वन भूमि की परिभाषा में आने के कारण नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है। अतः अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।
3)	Penalty should be imposed, as per guideline no 11-42/2017-FC dated 29.01.2018, on SECL for unauthorized diversion of forest land without prior approval.	उपरोक्तानुसार।
4)	The NPV for the entire 402.996 ha of forest land shall be deposited.	आवेदक विभाग द्वारा प्रत्याशा मूल्य की राशि रु. 29,41,65,180/- छत्तीसगढ़ कैम्पा में दिनांक 27/06/2018 को ई-चालान तैयार कर RTGS द्वारा जमा की गई है।  (संलग्नक-02)
5)	Compensatory afforestation shall be done on degraded forest land on double the forest land diverted and at least 1000 plants per ha will be planted (402.966 x 1000= 402966 plants) on the identified CA land with 10 years maintenance.  The cost of CA will be revised, if required, and the CA cost will be deposited in the Compensatory afforestation Fund managed by adhoc CAMPA.	आवेदक विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 53,21,11,767/- छत्तीसगढ़ कैम्पा में दिनांक 27/06/2018 को ई-चालान तैयार कर RTGS द्वारा जमा की गई है।  (संलग्नक-02)
6)	Penal CA will be done on degraded forest land on equal the forest land diverted illegally and at least 1000 plants per ha will be planted (402.966 x 1000= 402966 plants) on ,the identified penal CA land with 10 years maintenance. The cost of penal CA will be revised, if required, and the penal CA cost will be deposited in the Compensatory afforestation Fund managed by adhoc CAMPA.	आवेदक विभाग द्वारा दाण्डिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 26,60,55,884/- छत्तीसगढ़ कैम्पा में दिनांक 27/06/2018 को ई-चालान तैयार कर RTGS द्वारा जमा की गई है।  (संलग्नक-02)
7)	25% cost of the penal CA and CA cost will be deposited in addition to CA and penal CA for soil and moisture conservation works on the CA and penal CA sites.	आवेदक विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं दाण्डिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि 19,95,41,913/- छत्तीसगढ़ कैम्पा में दिनांक 27/06/2018 को ई-चालान तैयार कर RTGS द्वारा जमा की गई है।



		(संलग्नक-02)
8)	The user agency should undertake comprehensive greening in the villages located in the surrounding of their lease area.	वनमण्डलाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक विभाग द्वारा अधिरोपित शर्त के अनुसार राज्य वन विकास निगम द्वारा बाता गांव के 2.742 हे. राजस्व भूमि में वर्ष 2017-18 में 6855 नग फलदार वृक्षों का रोपण किया गया है। रोपित क्षेत्र में पौधे स्वस्थ हैं एवं जीवित प्रतिशत 90 प्रतिशत लगभग है।
9)	Mined out forest area already reclaimed by the User Agency, should be handed over back to the State Forest Department with a view to bring it under the ambit of core forestry management prior to stage II approval.	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (संलग्नक-03)
10)	The UA should prepare a land surrender schedule for surrender of the mined out and biological reclaimed forest land in accordance with the existing mine plan irrespective of progressive mine closure plan and submit a surrender schedule and an undertaking that mined out and biologically reclaimed forest land will be surrendered to the State Forest Department as per this schedule.	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (संलग्नक-04)
11)	Since the reclaimed forest land is revenue forest, the state government should notify the area as protected forest under Indian Forest Act or State Forest Act/rules. No further change in the schedule for surrendering of forest land should be allowed.	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (संलग्नक-05)
12)	With a view to enrich the water regime in the area, a comprehensive Catchment Area Treatment Plan in the area to arrest flow of silt in the Hasdeo River and to improve water regime should be implemented at the project cost. The plan along with detail financial outlay, duly approved by competent authority shall be submitted prior to stage II approval.	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (संलग्नक-06)
13)	A study should be undertaken at the project cost to assess the impact intervention undertaken by the SECL, in consultation with the State Forest Department, for the protection, conservation and development of wildlife in the area. Based on the outcome of such study, the measures for protection,	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (संलग्नक-07)



	conservation and development of the wildlife, if needed may further be strengthened at the project cost.	
14)	No forest land/Revenue Forest land should be used for rehabilitation and diversion of Right Bank Canal of Irrigation Department during the course for future mining expansion programme of the User Agency. The User Agency shall ensure that construction of residential accommodation for workers will be undertaken separately on non-forest land to avoid pressure on forest land for temporary construction;	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (संलग्नक-08)
15)	The staff working in the mine should be provided cooking gas through pipeline to avoid pressure on forests for fuel wood;	आवेदक विभाग द्वारा लेख किया गया है कि खदान में कार्यरत कर्मचारियों को को-आपरेटिव सोसायटी के माध्यम से एल.पी.जी. गैस प्रदाय किया जाता है ताकि खदान क्षेत्र से लगे हुये वन क्षेत्रों में किसी भी नुकसान और दबाव से बचा जा सके।
16)	A Monitoring Committee with DCF as one of its member, should be constituted to monitor the compliance of various conditions stipulated by the Government of India and implementation of reclamation plan;	वनमंडल स्तर पर समिति का गठन किया गया है एवं समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न हैं। (संलग्नक-09)
17)	Safety zone shall be fenced with coiled barbed wire fencing of 6 feet high for the protection of forests and boundary of the mining lease shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates;	व.म.अ. के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में सेफटीजोन प्लान्टेशन का कार्य 17 कि.मी. में से 03 कि.मी. किया गया है। जिसमें पौधों का जीवित प्रतिशत लगभग 95 प्रतिशत है। सेफटीजोन प्लान्टेशन का सुरक्षा घेराव चैनलिंग द्वारा किया गया है। शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गई है। (संलग्नक-10)
18)	User agency shall submit approved R&R plan and implement the R&R Plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government Regional Office of MoEF &CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.	आवेदक संस्था द्वारा पुर्नवास का कार्य कोल इंडिया लिमिटेड पुर्नवास निति 2012 तथा छ.ग. राज्य आर्दश पुर्नवास निति 2007 के अनुसार किया जा चुका है।
19)	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India topo-sheet of 1 :50,000 scale;	आवेदक विभाग द्वारा व्यपवर्तन प्रस्ताव के आवेदन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सर्वे आफ इंडिया टोपोशीट में चयनित क्षेत्र को दर्शाया गया है। (संलग्नक-11)



20)	<p>The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the <i>compensatory afforestation</i> at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State <i>through online portal</i>. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.</p>	<p>आवेदक विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 53,21,11,767/- छत्तीसगढ़ कैम्पा में दिनांक 27/06/2018 को ई-चालान तैयार कर RTGS द्वारा जमा की गई है। (संलग्नक-02)</p>
21)	<p>The User Agency shall transfer the funds for the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 through online portal of Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned;</p>	<p>आवेदक विभाग द्वारा प्रत्याशा मूल की राशि 29,41,65,180/- छत्तीसगढ़ कैम्पा में दिनांक 27/06/2018 को ई-चालान तैयार कर RTGS द्वारा जमा की गई है।</p>
22)	<p>Following activities shall be undertaken by the user agency at the project cost and if <i>appropriate cost of the plan/scheme shall be deposited in Ad-hoc CAMPA Account</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A plan containing appropriate Mitigative measures to minimize</li> <li>soil erosion and choking of streams shall be prepared and implemented;</li> <li>Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion;</li> <li>Construction of check dams, retention/ toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour;</li> <li>Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/benching so as to ensure that that angles of repose at any given place is less than 28°; and</li> <li>Strict adherence to the prescribed top soil management.</li> </ol>	<p>व.म.अ. के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक विभाग द्वारा तत् संबंध में लेख किया गया है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट योजना हेतु छत्तीसगढ़ कांसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी रायपुर को कार्यादेश जारी किया गया जा चुका है। संस्था द्वारा फाईनल रिपोर्ट जमा किया जा चुका है। तत्संबंध में आवेदक विभाग का वचन पत्र संलग्न है</li> <li>आवेदक विभाग ने छ.ग. राज्य वन विकास निगम के माध्यम से वर्ष 2006 से 2018-19 तक लगभग 203 हे. एरिया में रिक्लेम्ड माइंड आउट एरिया में लगभग 726094 नग पौधा रोपण एवं अन्य क्षेत्र में वर्तमान तक लगभग 493 हे. में 1909332 नग पौधा रोपण किया गया है। जिसमें जीवित प्रतिशत 80 से 90 तक है।</li> <li>आवेदक विभाग ने छ.ग.राज्य वन विकास निगम के माध्यम से वर्ष 2018-19 में रिक्लेम्ड माइंड आउट एरिया में भूमि क्षरण को रोकने में बोल्टर चेक डेम का निर्माण किया गया है।</li> <li>एस.ई.सी.एल. खुली खदान का कुल प्रस्तावित खनन क्षेत्र 1600.00 हे. है जिसमें से 30.09.19 तक लगभग 695 हे. में खनन कार्य पूर्ण हो चुका है। खनन</li> </ol>



		<p>की गई मिट्टी का डम्पर, डेजर एवं ग्रेडर आदि से 30.09.19 तक कुल 353 हे. क्षेत्र आंतरिक डम्प में एवं 196.242 हे. बाहरी डम्प में रिक्लेमेशन एवं टेरेसिंग किया जा चुका है।</p> <p>5. आवेदक विभाग द्वारा खनन के दौरान पृथक रूप से निकली टॉप सोइल की नियमित रूप से निर्धारित जगह पर संग्रहित कर प्रति वर्ष वृक्षारोपण से पूर्व उपयोग में लाया जाता है।</p>
23)	User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake afforestation on degraded forest land, one and half time in extent to the area used for safety zone;	<p>आवेदक विभाग द्वारा सेफटीजोन के 1.5 गुना बिगड़े वन क्षेत्र में वृक्षारोपण की राशि 1,18,84,392/- छत्तीसगढ़ कैम्पा में दिनांक 27/06/2018 को ई-चालान तैयार कर RTGS द्वारा जमा की गई है।</p> <p>(संलग्नक-02)</p>
24)	User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake <i>gap planting</i> and soil & moisture conservation activities to restock and rejuvenate the degraded open forests (having crown density less than 0.4), if any, located in the area within 100 meters from outer perimeter of the mining lease;	<p>व.म.अ. के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक विभाग द्वारा डम्प क्षेत्र में गैप प्लांटेशन वर्ष 2018-19 में एवं वर्ष 2019-20 में प्रतिवर्ष 50,000 नग पौधे रोपण किया जा चुका है।</p>
25)	User agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain. alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;	<p>आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।</p> <p>(संलग्नक-12)</p>
26)	The User Agency shall prepare a list of existing village tanks and other water bodies with GPS co-ordinates located within five km, from the mine lease boundary. This list is to be duly verified by the concerned Divisional Forest Officer. The User Agency shall regularly undertake de silting of these village tanks and other water bodies so as to mitigate the impact of siltation of such tanks/water bodies. A detailed plan for de silting of identified ponds and water bodies to be prepared in consultation with forest	<p>आवेदक विभाग द्वारा खनन क्षेत्र के 5 कि.मी. दूरी के परिधि में 17 गांवों में कुल 33 तालाब को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किये गये तालाबों का Desiltation आवेदक संस्था के व्यय पर किया जाना है। आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत Desiltation योजना संलग्न है।</p> <p>(संलग्नक-13)</p>




	department and shall be submitted to MoEF & CC before Stage-II approval;	
27)	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (संलग्नक-14)
28)	The user agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage- I clearance;	आवेदक विभाग द्वारा CA, NPV, PCA आदि की राशि छत्तीसगढ़ कैम्पा में दिनांक 27/06/2018 को ई-चालान तैयार कर RTGS के माध्यम से रु. 130,37,59,136/- जमा किया की गई है। (संलग्नक-2)
29)	User agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (protection) Act, 1986;	आवेदक विभाग द्वारा Environment Clearance की कॉपी प्रस्तुत की गई है। (संलग्नक-15)
30)	Fencing, protection and regeneration of the safety zone area [7.5 meters strip shall be kept within the mining lease boundary and area of the safety zone shall be part of the total area of mining lease as per the Ministry's guidelines dated 27.05.2015] shall be done at the project / cost within three years and maintained thereafter as per approved working plan of the State Govt. Besides this, afforestation on degraded forest land to be selected elsewhere measuring one & a half times the area under safety zone shall also be done at the project cost;	व.म.अ. के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक संस्था द्वारा वर्ष 2018-19 में सेफटीजोन प्लान्टेशन का कार्य 17 कि.मी. में से 03 कि.मी. किया गया है। जिसमें पौधों का जीवित प्रतिशत लगभग 95 प्रतिशत है। सेफटीजोन प्लान्टेशन का सुरक्षा घेराव चैनलिंग द्वारा किया गया है। शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (संलग्नक-16)
31)	The Forest clearance will be for a period co terminus with the lease period specified in the lease agreement. The State Government will submit the lease agreement document specified in the lease agreement;	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (संलग्नक-17)
32)	The user agency shall prepare a land surrender schedule for surrender of the mined out and biologically reclaimed forest land in accordance with the existing mine plan and progressive mine closure plan and submit an undertaking that mined out and biologically reclaimed forest land will be surrendered to the State Forest Department as per this schedule.	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (संलग्नक-18)
33)	User agency shall undertake mining in a phased manner and take due care for reclamation of the mined over area. The	व.म.अ. के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक संस्था द्वारा माईन क्लोजर प्लान में प्रस्तुत अनुमोदित योजना के तहत



	concurrent reclamation plan shall be executed by the User Agency as per the approved mining plan/scheme and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the concern Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, and the Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Central), Ministry of Environment & Forests, concern Regional Office. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the user agency, the Nodal Officer or the Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation activities are satisfactorily executed;	वर्षवार रिक्लेमेशन का कार्य किया जा रहा है। योजना संलग्न है। (संलग्नक-19)
34)	No labour camp shall be established on the forest land;	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (संलग्नक-20)
35)	Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (संलग्नक-21)
36)	State Government shall complete settlement of rights, in term of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in it's letter No. 11-9/1998-FC (pt.) dated 3rd August 2009 read with 05.07.2013, in support thereof;	व.म.अ. के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित वनक्षेत्र में शासन द्वारा वनअधिकार पत्र से संबंधित कार्यवाही पूर्ण कर लिया गया है एवं कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। आवेदक विभाग द्वारा कलेक्टर कोरबा से प्राप्त एफ.आर. ए. की कॉपी प्रस्तुत की गई है जो संलग्न हैं। (संलग्नक-22)
37)	The user agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional Office and this Ministry by the end of March every year regularly.	व.म.अ. के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक विभाग द्वारा लेख है कि वर्ष 2018-19 के लिये वार्षिक Self Compliance पत्र क्र. 42 दि. 26.04.19 के माध्यम से जमा किया जा चुका है। (संलग्नक-23)
38)	Any other condition that the concern Regional Office of this Ministry, may stipulate, from time to time, in the interest of conservation; protection and development of forests & wildlife; and	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (संलग्नक-24)
39)	The State Government and user agency shall comply the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है। (संलग्नक-25)



मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर से प्राप्त प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार (L.47 पृष्ठीय) पालन प्रतिवेदन  
(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित) २ प्रतियों में


  
(सुनील मिश्रा)  
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/ व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/खनिज/104 / 188

रायपुर, दिनांक 25/01/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- 1 मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- 2 वनमंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल, कटघोरा, छत्तीसगढ़।
- 3 मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल, कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

  
अ.प्र.मु.व.सं (भू-प्रबंध / व. सं. अ)  
01 छत्तीसगढ़